जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

उदयपुर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 28 संख्याः 19 प्रभात उदयपुर, रविवार 22 नवम्बर, 2020 आर.जे. 7202 पृष्ठ 8 मूल्य 1.20 रु.

रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू

जयपुर, 21 नवम्बर (कासं)। राजस्थान में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने 8 जिला मुख्यालयों पर रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया है। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा शामिल हैं। इन शहरों में बाजार, रैस्त्राँ, शॉपिंग मॉल व अन्य वाणिज्यिक संस्थान शाम 7 बजे तक ही खोले जा

- राज्य मंत्रिमंडल की आपात बैठक में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर व भीलवाड़ा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की
- इसके साथ ही मास्क नहीं पहनने पर 500 रु. जुर्माना वसूलने और बाजार शाम 7 बजे तक ही खुले रखने और विवाह समारोह में मात्र 100 लोगों की उपस्थिति की मंजूरी के आदेश भी दिए है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन 10 लाख संक्रमितों को वैक्सीन लगा चुका है!

पर चीन की वैक्सीन पूर्णतया ''टैस्टेड'' नहीं है, जिसके मरीज पर दूरगामी प्रभाव/दुष्प्रभाव क्या होंगे, कहना मुश्किल है

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 21 नवम्बर। वैक्सीन को लेकर, दो अलग-अलग किस्म के परिदृश्य उभर कर आ रहे हैं। जहाँ विकसित देशों में वैक्सीन संबंधी सुरक्षा का आकलन अभी तक चल ही रहा है, वहीं चीन में 10 लाख लोगों को ऐसी वैक्सीन दी जा चुकी हैं, जिनके बारे में अभी तरह सिद्ध नहीं हुआ था कि वे कारगर एवं सुरक्षित हैं।

इस प्रकार चीनी लोग खराब वैक्सीनेशन के जबरदस्त जोखिम में हैं।

फायज़र, जिसने सबसे पहले एक सफल वैक्सीन की घोषणा की थी, अब वैक्सीनेशन के प्रारम्भिक दौर के लिये, अमेरिकन फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (एफ.डी.ए.) से आपातकालीन वितरण (इमर्जेंसी डिस्पेन्सेशन) की अनुमति माँग रही है।

एफ.डी.ए., इस वैक्सीन को सार्वजनिक उपयोग के लिये जारी करने की अनुमति देने से पहले, इस वैक्सीन के सुरक्षित होने संबंधी तथा इसके साइड इफैक्ट्स के डेटा का परीक्षण-विश्लेषण करेगा। कंपनी ने कहा कि वह एफ.डी.ए. का अनुमोदन मिलने के 10 घंटे के अन्दर ही, इस वैक्सीन का वितरण शुरू करने की स्थिति में है।

- दूसरी ओर अमेरिका की फायज़र कंपनी, की वैक्सीन के ''ट्रायल व टैस्ट'' हो चुके हैं तथा कंपनी अमेरिका की सरकार पर दबाव लगा रही है, कि लालफीताशाही त्याग कर वैक्सीन को बाज़ार में बेचने की इज़ाजत दे दे। यह वैक्सीन जनवरी तक बिक्री के लिए बाज़ार में आ जायेगी।
- पर, भारत इसका लाभ नहीं उठा सकेगा आनन-फानन में, क्योंकि इसकी कीमत 60-70 डॉलर प्रति वैक्सीन है तथा उसे 70 डिग्री तापमान पर ही स्टोर किया जा सकता है। यह भारत में संभव नहीं, क्योंकि इतनी ''ड्राई-आईस'' (सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड) ही उपलब्ध नहीं है।
- एक और दिक्कत है, कि जिस संक्रमित को एक बार वैक्सीन का इंजेक्शन लग गया, चाहे वह वैक्सीन ''टैस्टेड'' हो या ''अनटैस्टेड', उस संक्रमित पर दूसरा वैक्सीन का इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता।
- अतः वैक्सीन लगाने के मामलों में भारत के समक्ष काफी दुविधा है, और केवल ''ऑक्सफोर्ड'' द्वारा विकसित वैक्सीन से ही आशा है।

एफ.डी.ए. अपना अनुमोदन दिसम्बर के पूर्वार्द्ध तक दे सकता है जिससे कि अगले वर्ष जनवरी से इसका वास्तविक वितरण शुरू हो सके। इसका अर्थ होगा- वैक्सीन के निर्माण की शुरूआती प्रक्रिया शुरू होने के 10 माह के अन्दर इसका वितरण शुरू हो जायेगा। यह अपने आप में एक असाधारण तथ्य माना जायेगा क्योंकि किसी वैक्सीन/दवा की निर्माण-प्रक्रिया की शुरूआत से लेकर वितरण प्रक्रिया शुरू होने में सामान्यतः 8 से 10 साल का समय लगता है।

किसी नई वैक्सीन को अंतिम रूप से जारी करने में इतना ज्यादा समय लगने का कारण होता है- इसके पूरी तरह सुरक्षित एवं निरापद होने के बारे में पूरी तरह आश्वस्त होना। किसी दवा को सार्वजनिक उपयोग के लिये जारी किये जाने से पहले, उसे क्लिनिकल ट्रायल तथा इसके साइड इफैक्ट्स के परीक्षण की कठोर एवं श्रमसाध्य प्रक्रिया से गुजरना होता है।

फायज़र के सी.ई.ओ. डॉ. अल्बर्ट बोरिआ ने कहा कि त्वरित वितरण के किया गया आवेदन ''दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध कराने के कंपनी के प्रयासों में मील का पत्थर था।'' लेकिन यह बात संदेहपूर्ण है कि दुनिया इसका उपयोग कितने समय तक कर पायेगी। वैक्सीन के बाजार में आने से संबंधित तमाम आशाओं और अपेक्षाओं के बावजूद,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नगरोटा मुठभेड़ पर पाक से जवाब तलब

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 21 नवम्बर। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग में उच्चायुक्त की एवज में काम-काज संभाल रहे अधिकारी को शनिवार को तलब कर दो दिन पूर्व नगरोटा में हुई मुठभेड़ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज किया।

भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जे.ई.एम.) द्वारा सुनियोजित आतंकी हमले के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की। जे.ई.एम. संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा भारत और कई देशों में प्रतिबंधित है।

- भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी अधिकारी को बुलाकर नगरोटा मुठभेड़ मामले पर कड़ी चेतावनी दी।

इस माह की 19 तारीख को जम्मू और कश्मीर के नगरोटा में भारतीय सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकवादी हमले को विफल किया था। अपनी जमीन से इस प्रकार के हमलों की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए उसे चेतावनी दी थी।

पाकिस्तान उच्चायोग के इस अधिकारी को दो टूक कहा गया, कि पाकिस्तान अपनी जमीन से संचालित हो रहे आतंकी संगठनों और आतंकवादियों का सहयोग करने की नीति से बाज आए और अन्य देशों में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान में करोना संक्रमण के अब तक के सभी रिकॉर्ड टूटे

राज्य में शनिवार को पहली बार एक ही दिन में अब तक के सर्वाधिक 3007 संक्रमित सामने आए हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 21 नवम्बर। प्रदेश में बेकावू होते करोना संक्रमण ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य में शनिवार को पहली बार एक ही दिन में अब तक के सर्वाधिक 3 हजार से ज्यादा संक्रमित सामने आए हैं। वहीं राजधानी जयपुर में भी रिकॉर्ड 551 संक्रमित मिले हैं। इस बीच प्रदेश में करोना से 16 और लोगों की मौत हो गई। उधर रिकवरी रेट भी 90 फीसदी से नीचे आ गई है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश के 32 जिलों में शनिवार को 3007 कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालाकि आज करौली जिले में संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि जयपुर में पिछले 6 दिनों में चार बार पांच सौ से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। उधर आज जोधपुर में 444, बीकानेर में 215, अजमेर में 210, कोटा में 203, अलवर में 139, भीलवाड़ा में 128, गंगानगर में 115, सीकर में 95, नागौर में 94, टोंक में 85, पाली में 84, उदयपुर में 82, भरतपुर में 56, चित्तौड़गढ़ में 55, बाड़मेर में 53, झुंझुनूं में 46, सवाई माधोपुर में 43, डूंगरपुर में 39, बारां में 31, दौसा में 30, बूंदी में 29, चूरू में 28, राजसमंद में 27, हनुमानगढ़ में

- राजधानी जयपुर में भी करोना संक्रमण के रिकॉर्ड 551 मामले मिले हैं।
- प्रदेश में करोना से रिकवर होने वाले मरीजों की दर 90 फीसदी से कम हुई, जबकि एक्टिव केस 9.12 प्रतिशत हो गए हैं।
- इस बीच राज्य में करोना संक्रमण से शनिवार को 16 और लोगों की मौत हो गई है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

14वीं बार सुनवाई टली

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 21 नवम्बर। विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए गोवा के एक दर्जन विधायकों के दो केसों की सुनवाई अब 26 नवम्बर को होगी क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) शरद अरविन्द बोबड़े की अध्यक्षता वाली जिस बैंच को सोमवार को इन केसों की सुनवाई करनी थी, वह उस दिन नहीं बैठ रही है।

कम्प्यूटर आधारित लिस्टिंग में अब कहा गया है कि अब इन केसों की

- गोवा में दलबदल करने वाले एक दर्जन विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी दो मामलों की सुनवाई 26 नवम्बर तक के लिए टल गई है। गौरतलब है कि इन सभी विधायकों ने भाजपा के पक्ष में दलबदल किया था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारतीय मूल की माला अडिगा, ''फर्स्ट लेडी'' की नीति सलाहकार नियुक्त

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 21 नवम्बर। भारतीय अमेरिकनों की प्रतिभा एवं योग्यता के प्रति सम्मान दर्शाने वाला एक और कदम उठाते हुये, अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने माला अडिगा को जिल बाइडन का पॉलिसी डायरैक्टर नियुक्त कर दिया है। ज्ञातव्य है कि 20 जनवरी 2021 को जिल बाइडन विधिवत अमेरिका की ''फर्स्ट लेडी'' (प्रथम महिला) बन जायेगीं। यह भारतीय अमेरिकनों के प्रति दर्शाया गया तीसरा सम्मान है- सबसे पहले कमला हैरिस को जो बाइडन के डिपुटी उप राष्ट्रपति पद के नामजद किया गया था तथा उसके बाद, डॉ. विवेक मूर्ति को बाइडन प्रशासन के कोविड-19 एडवाइजरी बोर्ड का सह-अध्यक्ष (को-चेयरमैन) बनाया गया था।

अडिगा, जिल बाइडन की वरिष्ठ सलाहकार तथा बाइडन- हैरिस प्रचार अभियान वरिष्ठ पॉलिसी एडवाइज़र रह चुकी हैं। इससे पहले वे, बाइडन फाउन्डेशन में हायर एजुकेशन एवं मिलिट्री फैमिलीज़ की निदेशक रह चुकी हैं। ग्रिनेल कॉलेज, युनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ पब्लिक हैल्थ तथा शिकागो विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल की स्नातक, माला अडिगा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के शासनकाल में, ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेअर्स में एकेडमिक प्रोग्राम्स डिप्टी असिस्टेंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेटस ऑफिस ऑफ ग्लोबल वीमैन्स में चीफ ऑफ स्टाफ एवं ऐम्बेसडर-ऐट-लार्ज की वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, वे नेशनल सिक्योरिटी स्टाफ (एन.एस.एस.) के मल्टीलेटरल एंड ह्यूमन राइट्स डायरेक्ट्रेट में मानवाधिकार निदेशक भी रह चुकी हैं। एन.एस.एस. में आने से पहले, वे न्याय विभाग में अटॉर्नी थी। यहाँ उन्होंने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के काउंसेल के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। कमला हैरिस की भांति अडिगा ने भी कानून की शिक्षा प्राप्त की है। वे शिकागो के किर्कलैण्ड एण्ड एल.एल.पी. में लिटीगेशन एसोसिएट थीं और उन्होंने वर्ष 2008 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की चुनाव मुहिम में शामिल होने से पूर्व इण्डियाना के उत्तरी जिले में जिला न्यायालय के जज फिलिप नियॉन के लिए लिपिक का काम किया था। उन्होंने ओबामा प्रशासन में अपना काम एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के काउन्सल के रूप में शुरू किया था। जो बाइडन ने जब वाइट हाउस स्टाफ के चार नए सीनियर सदस्यों की घोषणा

- कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने तथा डॉ. विवेक मूर्ति के कोविड-19 की सलाहकार समिति का को-चेयरमैन बनने के बाद अमेरिका के सर्वोच्च अधिकारियों की पंक्ति में माला तीसरी भारतीय हैं।
- डॉ. माला अडिगा भी कमला हैरिस की भांति वकील हैं, तथा ओबामा के प्रशासन में असिस्टैंट सेक्रेट्री ऑफ स्टेट थीं ब्यूरो ऑफ एजुकेशन व कल्चरल अफेयर्स में।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ना सिर्फ सचिन पायलट समर्थकों को दरकिनार किया जा रहा है, डोटासरा भी अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं

नगर निगम के चुनाव हों या जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव, डोटासरा की भूमिका बहुत सीमित रही है

जयपुर, 21 नवंबर (का.प्र.)। राजस्थान में 12 जिलों की 50 निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस ने नामांकन तिथि के 2 दिन पहले पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। कहा तो यह जा रहा है कि यह पर्यवेक्षक इन निकायों में जाकर वार्डवार तीन तीन नामों का पैनल तैयार करके उसके बाद उम्मीदवारी तय करेंगे, लेकिन कांग्रेस की 1998 के बाद से शुरू हुई परंपरा के अनुसार यह पर्यवेक्षक निकायों में सिर्फ पत्र वाहक की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में परंपरा डाल दी गई है कि विधायक या विधायक उम्मीदवार जो तय कर देंगे वही व्यक्ति सिंबल प्राप्त करके पार्टी का उम्मीदवार बन जाएगा। हाल ही में नगर निगम में हुए चुनाव में या फिर जिला परिषद और पंचायत समिति में टिकटों का वितरण हो,वहां भी पर्यवेक्षक तो बनाए गए, लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ सिंबल ले जाकर विधायकों को सौंपने तक की ही रही है।

अब 50 निकायों में होनेवाले चुनावों में जब टिकट वितरण विधायक या विधायक उम्मीदवारों की मर्जी से होना है, तो पर्यवेक्षकों की भूमिका सिंबल ले जाकर वहां देने तक की रह जाती है। ऐसे में पार्टी को चाहे संगठन स्तर पर कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, इस परंपरा को कांग्रेस बदलने को तैयार नहीं है। मजेदार बात तो यह भी है कि इस बार तो कांग्रेस ने उन विधानसभा क्षेत्रों में संगठन या विधानसभा चुनाव लड़े कांग्रेस के उम्मीदवारों को ही नकार दिया है, जिन क्षेत्रों में निर्दलीय विधायक हैं और उन्होंने सरकार का साथ दिया था। उन क्षेत्रों में निर्दलीय या बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के अलावा सरकार के साथ रहे अन्य पार्टियों के विधायकों के हिसाब से जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में सिंबल का वितरण किया गया है। कई विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां निर्दलीय और अन्य पार्टियों को तवज्जो देने के बाद कांग्रेस से जुड़े कई नेताओं ने बगावत का झंडा बुलंद किया है । ऐसे में समझा जा सकता है कि कांग्रेस में पर्यवेक्षक बनाना और उनकी भूमिका

- पर्यवेक्षकों की सूची मुख्यमंत्री खेमा तैयार करता है और पीसीसी उसे जारी करती है।
- यही कारण है कि नए प्रदेश अध्यक्ष आने के बाद से पीसीसी में सन्नाटा पसरा रहता है।
- पर्यवेक्षकों की भूमिका भी सिर्फ सिंबल ले जाकर विधायकों को सौंपने तक की नज़र आ रही है।
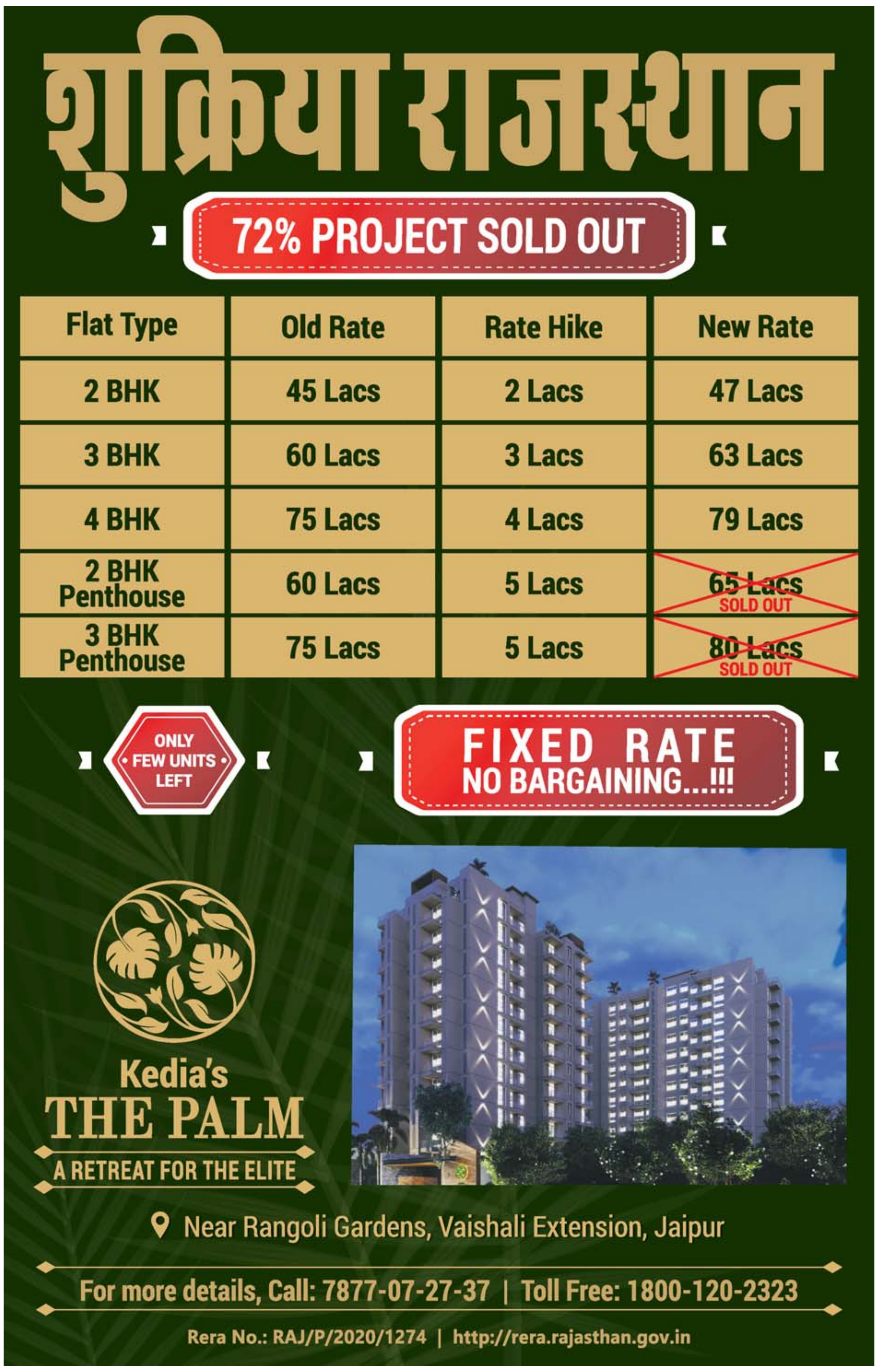
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)